Loan/given to Bombay Burmah Trading Corporation Limited by UTI and Commercial Banks

1668. SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH:

SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Bombay Burmah Trading Corporation Limited an associate company of Bombay Dyeing obtained a loan of Rs. 3 crores in 1985-86, Rs. 1 crore from Unit Trust of India and Rs. 2 crores from commercial banks;

(b) if so, whether it is a fact that the same loan was passed on to another subsidiary company known as Kachhaldara Trading Limited;

(c) if so, what are the details of the use made of the loan amount which was passed on to Kachhaldara Trading Limited from Bombay Burmah Trading Corporation; and

(d) whether it is legitimate to use loan for a purpose other than for which it is raised?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

आयकर की वसूली

1669. **श्री शरद यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने 1984 से आयकर के माध्यम से प्रतिवर्ष कितना-कितना धन वसूल करने का लक्ष्य रखा था ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रही है ;

(ग) क्या सरकार ने रुपयों में आयकर की चोरी की मात्रा का पता लगाने के लए कोई सर्वेक्षण कराया है ; और

(घ) यदि हां, तो यह अनुमानित राशि कितनी है तथा सरकार ने इसकी वसूली के लिए क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा) :(क) और (ख) :

(करोड़ रुपयों में)

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमानों के रूप में निर्धारित लक्ष्य	वास्तविक वसूलियां
1984–85	4314.00	4483.66
1985–86	4816.00	5374.30
1986–87	5711.00	6038.01
1987–88	6382.00	6644.00

(अनन्तिम)

उपर्युक्त आंकड़ों से यह पता चल सकता है कि वास्तविक वसूलियां सभी चार वर्षों के बजट अनुमानों से अधिक हैं ।

(ग) और (घ) देश में परिचालन में काले धन के कोई अधिकृत अनुमान उपलब्ध नहीं हैं । तथापि, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुरोध पर, राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान ने भारत में काले धन की अर्थव्यवस्था के कुछेक पहलुओं का अध्ययन किया था । मार्च, 1985 में प्रकाशित "ऐसपेक्ट आफ दि ब्लैक इकानामी इन इंडिया" नामक अपनी रिपोर्ट में, उन्होंने वर्ष 1983–84 के लिए काले धन की राशि 31,584 करोड़ रुपए से 36,786 करोड़ रुपए के बीच आंकी थी । तथापि, लेखकों ने यह स्वीकार किया कि उनके द्वारा लगाए अनुमान बहुत से पूर्वानुमानों और मोटे अनुमानों पर आधारित हैं और प्रत्येक को चुनौती दी जा सकती है ।

सरकार काले धन की उत्पत्ति, वृद्धि और उसके उपयोग को रोकने के लिए, समय-समय पर उपयुक्त समझे जाने वाले आवश्यक विधायी और प्रशासनिक उपाय कर रही है । इनमें से कुछ उपाय इस प्रकार हैं :—

(i) योजनाबद्ध सर्वेक्षण कार्रवाइयां ।

(ii) उपयुक्त मामलों में तलाशी और अभिग्रहण कार्रवाइयां ।

(iii) केन्द्रीय सूचना शाखाओं द्वारा सुनियोजित ढंग से सूचना की जांच-पड़ताल करना ।

(iv) नियंत्रणीय चुनिन्दा मामलों में गहन जांच करना ।

वित्तीय संस्थाओं से ऋण

1670. श्री शरद यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा 1984 से प्रति-वर्ष किस-किस वित्तीय संस्था से कितने-कितने ऋण कितनी-कितनी ब्याज दर पर लिए गए हैं ;

(ख) अगस्त, 1988 तक भारत पर कुल कितने रुपये का विदेशी कर्ज हो चुका है ;

(ग) 1984 से अब तक कितने रुपये के कर्जे का भुगतान किया जा चुका है ; और

(घ) 1984 से अब तक ब्याज के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया जा चुका है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवार्डो फलेरियो) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) से (घ) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट 148, अनुपत्र संख्या 77]**

Convening of an all-party meeting on Punjab problem

1671. SHRI TALARI MANOHAR: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi, convened an all party meeting to find out a solution to the Punjab problem; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) The Prime Minister visited Punjab on 21-9-1988 and announced that an all party meeting to discuss the Punjab problem would be held. A Cabinet Sub-Committee has since been constituted to work out details of the agenda for the meeting.

Setting up of an export monitoring cell at Hyderabad

1672. SHRI TALARI MANOHAR: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up an Export Monitoring Cell at Hyderabad; and

(b) if so, what functions are proposed to be assigned to this Cell?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. R. DAS MUNSHI): (a) and (b) While Government is keen to involve State Governments in exports, no specific scheme has yet been formulated to set up an Export Monitoring Cell in different States.